

भारत का गज़त्र

The Gazette of India

प्रसारण

EXTRAORDINARY

भाग II—पार्ट 3—उपचार (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ता० 488] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 30, 1974/अग्रहायण 9, 1896

No. 488] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30, 1974/AGRAHAYANA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रत्येक संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

ORDERS

New Delhi, the 30th November 1974

S.O. 681(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs—

- (a) that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make Orders to provide for the matters specified in clauses (d), (e), (f), (g), (h), (i), (ii) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation to all essential commodities, other than foodstuffs and fertilisers (whether inorganic, organic or mixed), be exercisable also by a State Government or, in relation to a Union territory, by the Administrator thereof, subject to the following conditions, namely:—
- (i) that the delegation of powers under clause (d) shall not extend to inter-State transport or distribution and the powers under that clause shall not be exercised so as to prejudicially affect such transport or distribution in pursuance of any Order issued by the Central Government;
 - (ii) that all Orders under clause (f) shall require the prior concurrence of the Central Government;
 - (iii) that no Order shall be issued in pursuance of the powers hereby delegated if it is inconsistent with any Order issued by the Central Government under the said Act;
 - (iv) that in making an Order relating to any of the matters specified in clause (j), the State Government or, as the case may be, the Administrator of a Union territory shall authorise only an officer of Government;

(b) that the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1844 dated the 18th June, 1968 issued under section 5 of the said Act shall stand rescinded:

Provided that, notwithstanding such rescission, any Order (hereinafter referred to as the said Order) made by a State Government or an administrator or any officer subordinate to that State Government or administrator in pursuance of the Order so rescinded and in force immediately before the commencement of this Order, shall be deemed to have been made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act, and shall continue in force according to its tenor, and accordingly any action taken or thing done (including any appointment made, licence or permit granted or direction issued) under the said Order and in force immediately before such commencement shall continue in force according to its tenor until and unless it is superseded by any action taken or anything done under any other Order made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act.

[No. 20(1)/74-CS.II]

उच्चोग और नागरिक पूति मंत्रालय

(नागरिक पूति और सहकारिता विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1974

का० शा० 681 (घ) .—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देनी है कि ---

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खण्ड, (घ) (ड), (च), (छ), (ज), (झ), (झम) और (झ) में विनियोगित विधियों की आवत्त उपबन्ध करने वा आदेश देने के लिए उसे जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उनका प्रयोग स्वाय पदाधं और उर्वरकों (चाहे वे अजेंब, जैव हाँ या मिथित हाँ) से भिन्न आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में, किसी गज्य सरकार द्वारा भी, या संघ गज्यसेवा में सम्बन्ध में, उसके प्रशासक द्वारा निम्नलिखित भांती के अधीन रहते हुए, किया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) कि खण्ड (घ) के अधीन जिन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है उनका विस्तार अन्तर्राजीय परिवहन या वितरण पर नहीं होगा और उस खण्ड के अधीन शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में ऐसे परिवहन या वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ;
- (ii) कि खण्ड (च) के अधीन सभी आदेशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति समेत होगी ;
- (iii) कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में, उस दण्डा में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब कि वह उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से असंगत हो ;
- (iv) कि खण्ड (झ) में विनियोगित विधियों में से किसी के सम्बन्ध में आदेश करने के लिए, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ गज्यसेवा का प्रशासक, सरकार के किसी अधिकारी को ही प्राधिकृत करेगा ;

(ब) उक्त अधिनियम को धारा 5 के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का आदेश मं० का० आ० 1844, तारीख 18 जून, 1966 विवरित हो जाएगा :

परन्तु ऐसे विवरण के होने हुए भी, इस प्रकार विवरण आदेश के अनुसरण में, किसी राज्य सरकार या प्रशासक या उस राज्य सरकार या प्रशासक के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) और जो इस आदेश के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त था, के बारे में यह गमना जाएगा कि उसे इस आदेश के अनुसरण में प्रीर उक्त अधिनियम की धारा 3 से सुसंगत उपबन्धों के अधीन किया गया है, और वह उसकी परिपक्वता कालावधि के अनुभार प्रवृत्त रहेगा और तदनुसार उक्त आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात (जिसमें की गई नियुक्ति, अनुदाता अनुशास्त्र या अनुज्ञापन या जारी किया गया निदेश सम्मिलित है) जो ऐसे प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी, अपनी परिपक्वता कालावधि के अनुभार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस आदेश के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 3 से सुसंगत उपबन्धों के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई किसी बात द्वारा उसे अधिकान्त नहीं किया जाता है।

[मं० 26 (1)/74-सी एस० II]

S.O. 682(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs—

- (a) that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make Orders to provide for the matters specified in clause (c) of sub-section (2) thereof shall in relation to all essential commodities, other than foodstuffs and fertilisers (whether inorganic, organic or mixed), be exercisable also by a State Government or, in relation to a Union territory, by the administrator thereof subject to the following conditions, namely:—
- (i) that where the price at which any essential commodity may be bought or sold is controlled by or under any other law for the time being in force, no Order shall be made in pursuance of the powers hereby delegated;
- (ii) that where the price is not so controlled, no Order shall be made in pursuance of the powers hereby delegated in respect of any essential commodity,—
- (A) if the whole-sale prices or retail prices, or both, of such commodity have been fixed by the manufacturers or producers thereof with the approval of Central Government, except on the basis of such prices;
- (B) in any other case, except with the prior concurrence of the Central Government;
- (iii) that no order shall be issued in pursuance of the powers hereby delegated if it is inconsistent with any Order issued by the Central Government under the said Act;
- (b) that the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2914 dated the 80th July, 1966 issued under section 6 of the said Act shall stand rescinded;

Provided that, notwithstanding such rescission, any Order (hereinafter referred to as the said Order) made by a State Government or an administrator or any officer subordinate to that State Government or